

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 935
दिनांक 08 फरवरी, 2024

पेट्रोल पर उपकर कम करने के लिए कदम

†935. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल पर उपकर और अधिभार को कम करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने पेट्रोल पर शुल्क में वृद्धि की है जबकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व में भी उतनी वृद्धि नहीं हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कुल क्रमशः 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य वैट कम कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर बुनियादी उत्पाद शुल्क तथा उपकर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपए/लीटर)

	पेट्रोल		डीजल	
	दिनांक 01.02.2021 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.02.2024 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.02.2021 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.02.2024 की स्थिति के अनुसार
बुनियादी उत्पाद शुल्क	1.4	1.4	1.8	1.8
सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी)	18	5	18	2

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पिछले तीन वर्षों के लिए राजकोष में पेट्रोलियम क्षेत्र के योगदान का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	केंद्रीय राजकोष को योगदान	राज्य राजकोष को योगदान
2020-21	4,55,069	2,17,650
2021-22	4,92,303	2,82,122
2022-23	4,28,067	3,20,651

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)